CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2025-8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

विकसित भारत @2047 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों का समन्वय

डॉ. नवीन कुमार मोक्टा
सहायक आचार्य
डॉ. प्रभात कुमार मिश्र
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली-110016
E-mail: navinmokta.ncert@gmail.com, prabhatkm@rediffmail.com, Mobile- 9816068848

First draft received: 05.12.2025, Reviewed: 09.12.2025
Final proof received: 15.12.2025, Accepted: 20.12.2025

शोध सार

विकसित भारत @2047 की परिकल्पना भारत को केवल आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो मानवीय मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों और लोकतांत्रिक चेतना पर आधारित हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से समग्र शिक्षा वह माध्यम है, जो विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को एक साथ आगे बढ़ाती है। यह शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के संदर्भ में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों के समन्वय का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में कक्षा तथा संस्थागत स्तर पर प्राप्त शैक्षिक अनुभवों के आधार पर दर्शन, समाजशास्त्र और शिक्षा के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के साथ-साथ कक्षा-स्तरीय तथा विद्यालय/महाविद्यालय-स्तर के व्यावहारिक उदाहरणों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों को शिक्षा से जोड़ते हुए यह शोध स्पष्ट करता है कि मूल्य-आधारित एवं संविधानोन्मुख शिक्षा विद्यार्थियों को केवल कुशल मानव संसाधन ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें संवेदनशील, उत्तरदायी और जागरूक नागरिक के रूप में भी विकसित करती है।

इस शोध-पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि शिक्षा प्रणाली में समग्रता, मानवीय दृष्टिकोण और संवैधानिक चेतना को प्रभावी रूप से शामिल किया जाए, तो विकसित भारत @2047 की संकल्पना को एक मजबूत नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक आधार प्राप्त हो सकता है। यह अध्ययन लेखक के शिक्षण एवं अकादमिक अनुभवों से प्रेरित वैचारिक-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

मुख्य शब्द- *विकसित भारत @2047, समग्र शिक्षा, मानवीय मूल्य, संवैधानिक आदर्श, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मूल्य आधारित शिक्षा, नागरिक चेतना आदि*

प्रस्तावना

भारत स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जहाँ वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" के निर्माण का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है (भारत सरकार, 2020; UNESCO, 2015)। यह लक्ष्य एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जो नैतिक, संवेदनशील, लोकतांत्रिक और समावेशी हो। इस व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो भावी पीढ़ी के विचार, व्यवहार और सामाजिक उत्तरदायित्व को दिशा देती है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहाँ एक ओर तकनीकी उन्नति और प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर मूल्य क्षरण, सामाजिक असहिष्णुता और नैतिक संकट जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं (UNESCO, 2015)। ऐसी स्थिति में शिक्षा का दायित्व केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि छात्रों में मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों के विकास तक विस्तृत हो जाता है। इसी संदर्भ में समग्र शिक्षा की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। समग्र शिक्षा छात्रों के बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास को एक साथ देखने पर बल देती है (Delors et al., 1996)। यह दृष्टिकोण छात्रों को केवल सक्षम मानव संसाधन ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक के रूप में भी विकसित करता है।

भारतीय संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श राष्ट्र की नैतिक नींव को मजबूत करते हैं (भारत का संविधान, 1950)। यदि इन संवैधानिक आदर्शों को शिक्षा के माध्यम से छात्रों के व्यवहार, सोच और निर्णय-प्रक्रिया से जोड़ा जाए, तो विकसित भारत @2047 का सपना अधिक सशक्त और टिकाऊ बन सकता है। इसी पृष्ठभूमि में यह शोध-पत्र समग्र शिक्षा के अंतर्गत छात्रों में मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों के समन्वय की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता, संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ताकि विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका को व्यापक दृष्टि से समझा जा सके।

विकसित भारत @2047: अवधारणा एवं लक्ष्य

भारत सरकार की "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना का उद्देश्य स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को केवल आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाना ही नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक रूप से समरस, न्यायपूर्ण और नैतिक रूप से उत्तरदायी समाज के रूप में विकसित करना भी है। यह अवधारणा केवल उद्योग, तकनीक या जीडीपी वृद्धि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानव विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने केंद्र में रखती है। विकसित भारत का आशय ऐसे समाज से है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलें, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो और वह अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सजग हो। इस परिकल्पना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार समझे जा सकते हैं - सामाजिक समरसता और समावेशन को बढ़ावा देकर एक समान, न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण, नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित कर लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना, नैतिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करते हुए संवैधानिक मूल्यों पर आधारित नागरिक संस्कृति का विकास, तथा ऐसे उत्तरदायी और संवेदनशील नागरिकों का निर्माण, जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझें और उन्हें निभाएँ।

इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा केवल रोजगार से जुड़े कौशल तक सीमित रह जाती है, तो विकसित भारत का

उद्देश्य अधूरा रह सकता है। इसके विपरीत, जब शिक्षा छात्रों में मानवीय मूल्यों, नैतिक चेतना और संवैधानिक आदर्शों का विकास करती है, तब वे केवल कुशल पेशेवर ही नहीं बनते, बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति जागरूक नागरिक के रूप में भी विकसित होते हैं।

समग्र शिक्षा: संकल्पना एवं उद्देश्य (NEP 2020 के संदर्भ में)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नया और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें शिक्षा को केवल किताबों की जानकारी या नौकरी से जुड़ी योग्यता तक सीमित नहीं माना गया है। इस नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और युवाओं का समग्र विकास करना है, ताकि वे केवल ज्ञानवान ही नहीं, बल्कि नैतिक, संवेदनशील, जिम्मेदार और संविधान के मूल्यों को समझने वाले अच्छे नागरिक बन सकें। NEP-2020 में समग्र शिक्षा का अर्थ है छात्रों का बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास एक साथ करना। यह शिक्षा बच्चों में सोचने-समझने की क्षमता, भावनाओं को समझने, सही-गलत का भेद करने, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और स्वस्थ जीवन जीने की आदत विकसित करती है। यही कारण है कि समग्र शिक्षा की यह अवधारणा "विकसित भारत @2047" के लक्ष्य से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि यह मानव-केंद्रित विकास पर जोर देती है और एक ऐसे समाज की नींव रखती है जहाँ विकास के साथ-साथ मानवीय मूल्य भी मजबूत हों।

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में **5+3+3+4** की संरचना अपनाई गई है, जिससे बच्चों को उनकी उम्र और विकासात्मक चरणों के अनुरूप सीखने का अवसर मिल सके (भारत सरकार, 2020)। इस स्तर पर समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता विकसित करना नहीं, बल्कि उनके भीतर नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता, सहनशीलता, सहयोग की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना है (NCERT, 2019)। पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को संविधान में निहित समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से परिचित कराया जाता है (भारत का संविधान, 1950)।

कहानियों, संवाद, समूह कार्य, कला, खेल और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे व्यवहारिक रूप से सीखते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करना, विचार साझा करना तथा परस्पर सम्मान देना सीखते हैं (UNESCO, 2015)। इस प्रकार विद्यालयी शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण अपनाकर छात्रों में लोकतांत्रिक व्यवहार और मानवीय सोच का विकास किया जाता है, जो उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में सहायता करता है (Delors et al., 1996)।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में समग्र शिक्षा - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में बहु-विषयक अध्ययन और बहु-प्रवेश–निर्गमन की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे छात्र केवल एक ही विषय तक सीमित न रहें। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज, संविधान और अपने नैतिक उत्तरदायित्वों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संवैधानिक अध्ययन, नैतिक और नागरिक शिक्षा, सामाजिक समस्याओं से जुड़े प्रोजेक्ट, सामुदायिक सहभागिता तथा फील्ड-वर्क को विशेष महत्व दिया गया है। इससे छात्र न केवल अपने विषय में दक्षता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए संवेदनशील, जागरूक और उत्तरदायी नागरिक के रूप में भी विकसित होते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक चेतना को भी मजबूत करती है।

समग्र शिक्षा और विकसित भारत @2047- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति या तकनीकी विकास से संभव नहीं है। इसके लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो मूल्य-आधारित, संविधानोन्मुख और मानव-केंद्रित हो। विद्यालयी और उच्च शिक्षा—दोनों स्तरों पर समग्र शिक्षा छात्रों को इस प्रकार तैयार करती है कि वे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दें और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करें। ऐसे शिक्षित नागरिक न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से समग्र शिक्षा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की एक मजबूत आधारशिला है। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर कार्य करने के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि समग्र शिक्षा के सिद्धांत व्यवहार में तभी प्रभावी होते हैं जब शिक्षक और संस्था दोनों इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाते हैं।

मानवीय मूल्य: अर्थ एवं शैक्षिक प्रासंगिकता

दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्य - मानवीय मूल्य किसी भी समाज की नैतिक चेतना, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार होते हैं शर्मा), 2015)। दार्शनिक दृष्टि से मानवीय मूल्य वे आदर्श हैं जो मानव व्यवहार को सत्य, करुणा, न्याय, समानता और सह अस्तित्व-) हैं करते मार्गदर्शित में दिशा कीBhattacharya, 2018)। भारतीय दर्शन में '*वसुधैव कुटुम्बकम्*', '*अहिंसा*' और '*धर्म*' जैसी अवधारणाएँ व्यक्ति को समाज और प्रकृति से जोड़ते हुए मानवीय मूल्यों की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करती है) Radhakrishnan, 1951)। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानवीय मूल्य सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों को दिशा देने वाले तत्व हैं। ये मूल्य समाज में सहयोग, सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं)Verma, 2022)। जब समाज में मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, तो उसका परिणाम सामाजिक असंतुलन, हिंसा और असहिष्णुता के रूप में सामने आता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है)UNESCO, 2015)।

शैक्षिक दृष्टि से मानवीय मूल्य शिक्षा के नैतिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह छात्रों के चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और सामाजिक संवेदनशीलता को विकसित करने का प्रभावी माध्यम भी है (Delors et al., 1996)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल कुशल कार्यबल तैयार करना नहीं, बल्कि अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है (भारत सरकार, 2020)।

कक्षा एवं छात्र व्यवहार के संदर्भ में मानवीय मूल्य - कक्षा शिक्षा का वह जीवंत सामाजिक स्थान है जहाँ मानवीय मूल्य केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के व्यवहार में विकसित होते हैं। छात्रों का आपसी संवाद, समूह में कार्य करना, अनुशासन का पालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया-इन सभी में मानवीय मूल्यों की झलक दिखाई देती है। जब शिक्षक संवादात्मक, सहभागितापूर्ण और संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों को अपनाते हैं, तब कक्षा में सहयोग, सम्मान, सहानुभूति और समानता जैसे मूल्य स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। समूह कार्य के माध्यम से छात्र सहयोग और सह-अस्तित्व सीखते हैं, कक्षा संवाद उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता और दूसरों की बात सुनने का सम्मान सिखाता है, तथा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए छात्रों के साथ समान व्यवहार से उनमें समानता और सामाजिक न्याय की समझ विकसित होती है। इस प्रकार कक्षा में विकसित मानवीय मूल्य छात्रों को केवल अनुशासित विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, सहनशील और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में तैयार करते हैं।

मानवीय मूल्य और विकसित भारत @2047 - विकसित भारत @2047 की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है, जब आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ-साथ नैतिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से उत्तरदायी भी हो। दर्शन, समाजशास्त्र और शिक्षा—इन तीनों के समन्वय से विकसित मानवीय मूल्य छात्रों में संवैधानिक आदर्शों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता की भावना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की क्षमता विकसित करते हैं। जब शिक्षा के माध्यम से छात्र सत्य, न्याय, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को व्यवहार में अपनाते हैं, तब वे केवल अपने व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मानवीय मूल्यों की शैक्षिक प्रासंगिकता केवल नैतिक शिक्षा तक सीमित न रहकर, विकसित भारत के दीर्घकालिक और टिकाऊ निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती है। कक्षा में समूह कार्य, संवाद और सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों के व्यवहार में इन मूल्यों की व्यावहारिक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

संवैधानिक आदर्श एवं शिक्षा

भारतीय संविधान के संदर्भ में संवैधानिक आदर्श- भारतीय संविधान देश की नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक भावना का आधार है। संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करते हैं। ये आदर्श केवल सरकार और शासन व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए भी मार्गदर्शक हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे संविधान और उसकी संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखें, समाज में सद्भाव, वैज्ञानिक सोच और मानवीय संवेदनशीलता को बढ़ावा दें तथा पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक आदर्श केवल अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि नागरिकों में नैतिक चेतना, कर्तव्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने पर भी जोर देते हैं।

कक्षा, पाठ्यक्रम एवं NEP-2020 के संदर्भ में संवैधानिक आदर्श - संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों में संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक सोच और नागरिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना भी है। कक्षा के स्तर पर इन आदर्शों को पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु, चर्चा और संवाद, वाद-विवाद, समूह गतिविधियों, परियोजना कार्य तथा सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। जब कक्षा में सभी छात्रों के साथ समान और समावेशी व्यवहार किया जाता है, तो उनमें न्याय और समानता की समझ विकसित होती है। विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर देने से स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जबकि समूह कार्य और साझा जिम्मेदारियों से बंधुत्व की भावना मजबूत होती है। NEP-2020 के अंतर्गत मूल्य-आधारित शिक्षा, नागरिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और सेवा-आधारित अधिगम पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे छात्र संवैधानिक आदर्शों को केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में भी अपनाएँ।

संवैधानिक आदर्श, शिक्षा एवं विकसित भारत @2047 - विकसित भारत @2047 की परिकल्पना ऐसे नागरिकों की अपेक्षा करती है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदार हों (नीति

आयोग, 2022)। जब शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक आदर्शों को छात्रों के जीवन से जोड़ा जाता है, तो उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता विकसित होती है (भारत सरकार, 2020)। ऐसे शिक्षित नागरिक न केवल अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचते हैं, बल्कि समाज और देश के व्यापक हितों के लिए भी कार्य करते हैं (UNESCO, 2015)। इस प्रकार शिक्षा और संविधान का यह गहरा संबंध विकसित भारत के निर्माण में नैतिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से संतुलित समाज की मजबूत नींव तैयार करता है (भारत का संविधान, 1950)।

समग्र शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों का समन्वय

समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनके जीवन में मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारना है (Delors et al., 1996)। यह समन्वय तभी प्रभावी हो सकता है, जब शिक्षा प्रक्रिया को केवल सैद्धांतिक न रखकर कक्षा स्तर से लेकर विद्यालय और संस्थागत स्तर तक निरंतर और सुनियोजित रूप से लागू किया जाए (भारत सरकार, 2020)। जब शिक्षा छात्रों की सोच, व्यवहार और निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तभी वे नैतिक, संवेदनशील और संविधान के मूल्यों को मानने वाले जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो पाते हैं (Sharma, 2015)। इस प्रकार समग्र शिक्षा, शिक्षा और जीवन के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है (UNESCO, 2015)।

कक्षा-स्तरीय मॉडल- कक्षा शिक्षा का वह मूल स्तर है जहाँ छात्रों में मानवीय मूल्यों और संवैधानिक चेतना का वास्तविक विकास संभव होता है (NCERT, 2019)। कक्षा-स्तरीय मॉडल के अंतर्गत संवाद आधारित शिक्षण के माध्यम से छात्रों को अपनी बात कहने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे स्वतंत्रता और सम्मान जैसे संवैधानिक आदर्श विकसित होते हैं (भारत का संविधान, 1950)। सहयोगात्मक अधिगम से छात्रों में सह-अस्तित्व, बंधुत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होती है (Delors et al., 1996)।

स्थितिजन्य अध्ययन और नैतिक द्वंद्व से जुड़े प्रश्न छात्रों को न्याय, समानता और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाते हैं (Verma, 2022)। वहीं समावेशी कक्षा व्यवहार विविध सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करता है, जो समानता और सामाजिक न्याय का प्रत्यक्ष अभ्यास है (UNESCO, 2015)। इस मॉडल में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि एक फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) की भूमिका निभाता है, जो छात्रों को मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है (भारत सरकार, 2020)।

विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के उदाहरण - विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा को संस्थागत संस्कृति का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके लिए मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों जैसे वाद-विवाद, नाटक, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से अपनाया जा सकता है। छात्र परिषद, बाल संसद तथा एनएसएस और एनसीसी जैसी इकाइयों के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नागरिक कर्तव्यों का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। सेवा-आधारित अधिगम के माध्यम से छात्रों को समुदाय की वास्तविक समस्याओं से जोड़ा जाता है, जिससे उनमें करुणा, सामाजिक उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता विकसित होती है। इसके साथ ही, जब किसी संस्था की नियम-प्रणाली, अनुशासन और निर्णय-प्रक्रिया संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप संचालित होती है, तो वह छात्रों के लिए एक सकारात्मक मूल्य-पर्यावरण का निर्माण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहु-विषयक पाठ्यक्रम, परियोजना आधारित अधिगम और सामुदायिक जुड़ाव छात्रों को संवैधानिक मूल्यों का जीवंत-व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं।

समन्वय का प्रभाव: विकसित भारत @2047 की दिशा में - कक्षा-स्तरीय मॉडल और विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के संस्थागत प्रयासों के समन्वय से विद्यार्थियों में मानवीय संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक सोच और नागरिक उत्तरदायित्व का समग्र विकास होता है। यह प्रक्रिया छात्रों को केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें नैतिक रूप से जागरूक और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक के रूप में भी तैयार करती है। जब शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्य और संवैधानिक आदर्श विद्यार्थियों के व्यवहार का हिस्सा बनते हैं, तब वे समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार समग्र शिक्षा के माध्यम से मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों का यह समन्वय विकसित भारत @2047 की संकल्पना को वास्तविक और व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। यह समन्वय केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि कक्षा और संस्थागत स्तर पर निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि शैक्षिक संस्थानों में दैनिक कार्यप्रणाली के दौरान देखा जा सकता है।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

समग्र शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों का प्रभावी समन्वय एक दीर्घकालिक एवं बहु-आयामी प्रक्रिया है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करती है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में अनेक नीतिगत, संस्थागत एवं शिक्षक-स्तरीय चुनौतियाँ विद्यमान हैं। साथ ही, इन चुनौतियों के भीतर ही विस्तृत संभावनाएँ भी निहित हैं।

नीतिगत स्तर की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ- नीतिगत स्तर पर समग्र शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती नीति और व्यवहार के बीच मौजूद अंतर की है, क्योंकि मूल्य-आधारित और संवैधानिक शिक्षा को आज भी प्रायः सैद्धांतिक दस्तावेजों तक सीमित मान लिया जाता है। इसके साथ ही परीक्षा-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और नागरिक मूल्यों का प्रभावी आकलन एक जटिल कार्य बना हुआ है, जिससे इनके व्यवहारिक पक्ष को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित लचीलापन, बहु-विषयक दृष्टिकोण तथा अनुभवात्मक अधिगम की अवधारणा मूल्य-आधारित शिक्षा को व्यवहार में उतारने की व्यापक संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। यदि नीतिगत स्तर पर मूल्य एवं नागरिक शिक्षा को पाठ्यचर्या का अनिवार्य और समेकित अंग बनाया जाए, तो यह न केवल शिक्षा प्रणाली को अधिक मानवीय बनाएगी, बल्कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को भी एक सुदृढ़ और टिकाऊ आधार प्रदान कर सकेगी।

संस्थागत स्तर की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रायः अकादमिक उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि मूल्य-आधारित गतिविधियों को सहायक या गौण मान लिया जाता है, जो समग्र शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में एक प्रमुख चुनौती बनती है। इसके अतिरिक्त संसाधनों की कमी, समय-सीमा का दबाव तथा प्रशासनिक औपचारिकताएँ भी संस्थागत स्तर पर मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तथापि, यदि संस्थागत स्तर पर समावेशी शैक्षिक वातावरण विकसित किया जाए, छात्र सहभागिता तंत्र को सशक्त बनाया जाए तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाए, तो मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। जब विद्यालय और महाविद्यालय स्वयं संवैधानिक संस्कृति के आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, तब छात्रों में मूल्य-आधारित व्यवहार का स्वाभाविक और स्थायी विकास संभव हो पाता है।

शिक्षक-स्तर की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ- शिक्षकों के स्तर पर समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के अभाव की है, जिसके कारण अनेक शिक्षक मूल्य-आधारित शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम से अलग मानते हैं और उसका समावेश कक्षा में सीमित रह जाता है। इसके अतिरिक्त बढ़ता हुआ कार्यभार और मूल्यांकन से जुड़ा दबाव शिक्षकों की रचनात्मकता और नवाचार क्षमता को भी प्रभावित करता है। दूसरी ओर, शिक्षक समग्र शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख परिवर्तनकर्ता की भूमिका निभाते हैं और यदि उन्हें संवैधानिक मूल्यों, मानवीय दृष्टिकोण तथा संवादात्मक और सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धतियों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे कक्षा को एक लोकतांत्रिक, संवेदनशील और सहभागी स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षक का आचरण और व्यवहार स्वयं छात्रों के लिए एक जीवंत मूल्य-आदर्श बनता है, जिससे मानवीय मूल्यों और संवैधानिक चेतना का स्वाभाविक विकास संभव हो पाता है।

विकसित भारत @2047 के संदर्भ में समेकित दृष्टिकोण- नीतिगत, संस्थागत एवं शिक्षक-स्तर की चुनौतियों और संभावनाओं का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि समग्र शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोगात्मक एवं बहु-स्तरीय दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि इन तीनों स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो शिक्षा प्रणाली विकसित भारत @2047 के निर्माण में एक नैतिक, लोकतांत्रिक एवं मानव-केंद्रित आधार प्रदान कर सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष- विकसित भारत @2047 की परिकल्पना एक ऐसे राष्ट्र की आकांक्षा को सामने रखती है, जो केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित न होकर सामाजिक समावेशन, नैतिक दृढ़ता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। इस व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही वह आधार है जिसके माध्यम से भावी नागरिकों के विचार, व्यवहार और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित होते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि समग्र शिक्षा विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों के समन्वय का एक प्रभावी माध्यम है।

दर्शन, समाजशास्त्र और शिक्षा के अंतर्संबंध के संदर्भ में यह अध्ययन यह संकेत देता है कि मूल्य-आधारित एवं संविधानोन्मुख शिक्षा छात्रों को केवल अकादमिक रूप से सक्षम नहीं बनाती, बल्कि उनमें संवेदनशीलता, विवेकशीलता और लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास करती है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सशक्त वैचारिक ढाँचा प्रदान करती है, तथापि इसका वास्तविक प्रभाव तभी संभव है जब इसके सिद्धांतों को कक्षा-स्तर, संस्थागत स्तर और शिक्षक-स्तर पर व्यवहारिक रूप से अपनाया जाए। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समग्र शिक्षा विकसित भारत @2047 की संकल्पना को एक ठोस नैतिक और मानवीय आधार प्रदान करती है। यह निष्कर्ष लेखक के अध्ययन, शिक्षण अनुभव तथा नीति-दस्तावेजों के समालोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है।

नीतिगत सुझाव- नीतिगत स्तर पर यह आवश्यक है कि शिक्षा नीतियों में मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उन्हें अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया जाए, ताकि मूल्य-आधारित शिक्षा केवल वैकल्पिक या सहायक गतिविधि न रह जाए। इसके साथ ही मूल्य-आधारित शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परीक्षा-केंद्रित आकलन के स्थान पर वैकल्पिक और गुणात्मक आकलन उपकरण विकसित किए जाने चाहिए, जो छात्रों के

व्यवहार, दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व को माप सकें। साथ ही विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा—दोनों स्तरों पर नागरिक शिक्षा और संवैधानिक साक्षरता को सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिससे छात्र अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझें और लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात कर सकें।

शैक्षिक सुधार हेतु सुझाव - शैक्षिक सुधार की दिशा में यह आवश्यक है कि कक्षा शिक्षण में संवादात्मक, सहभागितापूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता दी जाए, जिससे छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में जुड़ सकें। विद्यालयों और महाविद्यालयों को स्वयं संवैधानिक मूल्यों के जीवंत मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ संस्थागत संस्कृति, नियम और व्यवहार लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करें। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिनमें मूल्य-आधारित तथा संविधानोन्मुख शिक्षण पद्धतियों पर विशेष बल दिया जाए, ताकि वे कक्षा में इन मूल्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों, सामुदायिक सेवा और परियोजना कार्य को पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाकर शिक्षा को समाज और जीवन से जोड़ा जा सकता है, जिससे छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक उत्तरदायित्व का विकास हो सके।

भविष्य के शोध की दिशा- भविष्य के शोध के लिए समग्र शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण दिशा हो सकता है। ऐसे अध्ययनों के माध्यम से यह समझना संभव होगा कि मूल्य-आधारित शिक्षा छात्रों के व्यवहार, सोच और नागरिक चेतना को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके साथ-साथ विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर मूल्य-आधारित शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन भी किए जा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर इसके प्रभाव और व्यावहारिक चुनौतियाँ क्या हैं। इसी क्रम में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में संवैधानिक मूल्यों के शैक्षिक प्रभावों पर शोध की भी आवश्यकता है, ताकि यह समझा जा सके कि विविधता से भरे भारतीय समाज में शिक्षा लोकतांत्रिक और संवैधानिक चेतना को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि विकसित भारत @2047 का निर्माण केवल नीतियों और योजनाओं के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए शिक्षा के द्वारा नैतिक, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों का समन्वय भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और मानव-केंद्रित राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ सूची

हिंदी स्त्रोत

1. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय दिल्ली.
2. नीति आयोग. (2022). *विकसित भारत @2047 : दृष्टि पत्र*. भारत सरकार, राष्ट्रीय दिल्ली.
3. भारत सरकार. (1950). *भारत का संविधान*. विधि मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय दिल्ली.
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2019). *विद्यालयी शिक्षा में मूल्य शिक्षा*. एनसीईआरटी, राष्ट्रीय दिल्ली.
5. शर्मा, एस. आर. (2015). *भारतीय शिक्षा में नैतिक एवं मानवीय मूल्य*. प्रकाशन संस्थान, राष्ट्रीय दिल्ली.
6. सिंह, एम. एस. (2017). *मूल्य शिक्षा: अवधारणा एवं व्यवहार*. पियर्सन इंडिया, राष्ट्रीय दिल्ली.
7. कुमार, एन. (2021). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा की अवधारणा*. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 6(2), 45–56.
8. वर्मा, आर. (2022). *संवैधानिक मूल्य एवं शिक्षा का अंतर्संबंध*. शिक्षा विमर्श प्रकाशन, लखनऊ.

अंग्रेज़ी स्त्रोत

9. UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing, Paris, France.
10. Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley, M., Quero, M. P., Savane, M. A., Singh, K., Stavenhagen, R., Suhr, M. W., & Nanzhao, Z. (1996). *Learning: The treasure within* (Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century). UNESCO Publishing, Paris, France.
11. Mishra, R. (2023). *Holistic education and citizenship development in India*. Routledge India, New Delhi, India.

संदर्भ (जर्नल्स / पीरियॉडिकल्स)

12. Compare: A Journal of Comparative and International Education. Routledge, London, United Kingdom.
13. International Review of Education. UNESCO Institute for Lifelong Learning & Springer, Hamburg, Germany.
14. Prospects: Quarterly Review of Comparative Education. UNESCO & Springer, Paris, France.
15. Journal of Moral Education. Journal of Moral Education. Routledge, London, United Kingdom.
16. Indian Educational Review. National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi, India.
17. Journal of Values Education. Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, India.
18. University News. Association of Indian Universities (AIU), New Delhi, India.
19. Indian Journal of Educational Research. Educational Research Association of India, New Delhi, India.